RAJYA SABHA

(Tuesday, the 14th July, 1998/ 23, Asadha 1920/Saka)

The House met at eleven of the clock:

Mr. Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मांग पर टेलीफोन

*381. **श्री राम गोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आम जनता को मांग पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना निर्णय हेतु लम्बित है, और

(ख) यदि हां, तो मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने संबंधी समय सीमा क्या है?

संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में यह परिकल्पना की गयी थी कि वर्ष 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जाएंगे जिसमें दूरसंचार विभाग के प्रयासों में प्राइवेट क्षेत्र का सहयोग होगा। टेलीफोन की मांग पूर्ववर्ती अनुमानों की तुलना में अधिक हो गयी और बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की प्रविष्टि में भी विलम्ब हो गया। इस प्रकार वर्ष 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

दूरसंचार विभाग ने योजना आयोग के समक्ष 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के प्रस्तावों की अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सरकार के प्रयासों में प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मांग पर टेलीफोन प्रदान कर दिये जाने की परिकल्पना की गयी है।

छः सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए छः प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। इनमें से एक कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश में सेवा प्रारंभ कर दी गयी है।

श्री राम गोपाल यादव: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का जवाब दिया है, उसे आप सबने सुना है। इसी प्रश्न के जवाब का जो एक पैरा है, बिल्कुल यही जवाब 19 नवम्बर, 1997 के अनस्टार्ड क्वैश्चन नंबर 25 में संचार मंत्री जी ने दिया था और आप देखेंगे कि उसमें कौमा और फुलस्टॉप में भी कोई अन्तर नहीं है—

> "Department of Telecommunications has submitted 9th Five Year Plan proposals to the Planning Commission for approval which envisage provision of telephone on demand by the end of the 9th Five Year Plan with private sector supplementing the efforts of the Government."

श्रीमन्, सवाल यह है कि 8 महीने बाद भी क्या प्रश्न का जवाब वही होगा और नवीं पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष बीतने के बाद भी क्या प्लानिंग कमीशन प्रपोजल पर कोई सहमति या असहमति व्यक्त नहीं करती है? मैं यह जानना चाहूंगा। अब जबकि पिछले वर्षों में रेट आफ ग्रोथ आफ सबस्क्राइबर जो है वह हिन्दुस्तान में 22 और 23 फीसदी के लगभग है। जब इतनी तेजी से सबस्क्राइबर की वृद्धि होगी और किसी मामले के क्रियान्वयन में इतना विलंब होगा तो क्या नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए 50 परसेंट भी उस पर अमल हो सकेगा? क्योंकि अभी भी जो लक्ष्य हर वर्ष निर्धारित किया जाता है उसका 70 परसेंट, 75 परसेंट और 80 परसेंट भी पूरा नहीं हो पाता है। यह आपकी 22 परसेंट वृद्धि हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक यह जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि प्लानिंग कमीशन के लिए जो आपने एक प्रपोजल देना है या योजना भेजी है, उसमें कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उस पर गवर्नमेंट एप्रूवल नहीं दे पा रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जो सवाल फैक्चुअल पूछा जाएगा, उसका जवाब एक वर्ष बाद भी और 10 वर्ष बाद भी वही होगा। यही कन्सिसटेंसी डिमांड करती है कि फैक्चुअल चीज का जवाब वही हो, इसलिए जिस पैरा का उन्होंने जिक्र किया, वह केवल फैक्चुअल है। जहां तक लक्ष्य का सवाल है, आपकी सप्लीमेंटरी का भरपूर जवाब दूंगी, नवीं पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 37 लाख की डिमांड आंकी गई थी, उस 2 करोड़ 37 लाख के विरुद्ध 1 करोड़ 85 लाख डीओटी, डिपार्टमेंट आफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपना दायित्व माना था और 52 लाख प्राइवेट

आपरेटर के लिए रखा था। मैं आपके माध्यम से जवाब देते हुए संसद सदस्य को, पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं 80 परसेंट, 90 परसेंट भी पूरा नहीं होता, तो मुझे खुशी होती है यह कहते हुए कि पहले वर्ष में, इस 9वीं योजना के पहले वर्ष में डीओटी को 29 लाख टेलीफोन देने थे, उसके अगेन्स्ट 80 या 90 परसेंट नहीं, बढ़ाकर 32 लाख टेलीफोन हमने दिए यानि 3 लाख ज्यादा।

और इस वर्ष भी, सभापति जी, हमारा इस वर्ष का लक्ष्य है, वह टारगेट 33 लाख रखा गया था और हमने उसको 36 लाख किया है और इस वर्ष भी हम 36 लाख देंगे। इसलिए 80-90 परसेंट नहीं, बल्कि 125 परसेंट की वृद्धि डीओटी कर रहा है।

श्री रामगोपाल यादव: सर, यह सही है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, उसका जवाब फैक्चुअल होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भी फैक्चुअल आंसर यही न हो कि योजना प्लानिंग कमीशन के यहां विचाराधीन है। अगर यही है तो फैक्चुअल आंसर का कोई अर्थ नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं रहता और न ही जनता को उसका कोई लाभ मिल सकता है।

आपने कहा है कि 6 प्राइवेट कम्पनियों ने लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं और उनमें से एक ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लाइसेंस एग्रीमेंट कब साइन हुए थे? क्या इनमें ऐसी कम्पनियां भी हैं जिनको लेकर आप लोगों ने और हम सब ने काफी दिनों तक हाउस नहीं चलने दिया था?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मेरे द्वारा उनके पहले पूरक प्रश्न का जवाब देने के बाद उनके दूसरे पूरक प्रश्न के पहले भाग का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वह कतई इरेलिवेंट है। जब मैं कह रही हूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा है, उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यह फैक्चुअल जवाब कैसे रहेगा। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि 2002 में भी मैं इस सदन में खड़ी होकर कह सकूं कि जो लक्ष्य हमने रखा था, उससे ज्यादा हमने एचीव कर लिया है, इस प्रगति और गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक आपने प्राइवेट आपरेटर्स के बारे में सवाल किया है, तो मैं बताना चाहती हूं कि वे कम्पनियां 6 हैं। सभापति जी, मैं इनके पूरक प्रश्न के भाग दो का जवाब दे रही हूं। भारती टेलिकॉम, जो मध्य प्रदेश के लिए आ रही है, रिलायन्स टेलिकॉम गुजरात के लिए, युग इस्पात महाराष्ट्र के लिए, एस्सार पंजाब के लिए, टाटा टेलि सर्विसिज़ आन्ध्र प्रदेश के लिए और टेलिलिंक नेटवर्क इंडिया लिमिटेड राजस्थान के लिए। जहां तक सवाल यह है कि क्या ये कम्पनियां वही हैं, तो निश्चित तौर पर कम्पनियां वही हैं क्योंकि मेरे आने के बाद तो किसी कम्पनी से एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है और पुराने समय के साइन किए हुए एग्रीमेंट उन्हीं कम्पनियों के साथ हैं जो कम्पनियां उस समय थीं। इसका जवाब राम गोपाल जी को मालूम ही है, लेकिन सदन में यदि ये कहलवाना चाहते हैं तो मैंने 6 की 6 कम्पनियों का नाम दे दिया है। निश्चित ही ये कम्पनियां वही हैं जिनका एग्रीमेंट उस वक्त साइन हुआ था।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, मंत्री जी ने जो बात कही है कि वे उपभोक्ताओं को टेलीफोन उपलब्ध करा सकने में पूरी तौर पर सफल हुई है, इस बारे में मैं कह सकता हूं कि जहां तक शहरी उपभोक्ताओं की बात है, वे अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इस मंत्रालय ने एक और दायित्व लिया था, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने का। उस संदर्भ में इस मंत्रालय की जो स्थित है वह निश्चित रूप से बहुत कमजोर है, ऐसी मेरी जानकारी है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे स्पष्ट करें कि क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन स्थापित करने के लिए और आज स्थिति क्या है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, नरेन्द्र मोहन जी की जानकारी बिल्कुल सही है कि वी०पी० टीज़० का जो लक्ष्य रखा गया था वह 50 प्रतिशत के लगभग ही पूरा हुआ है, बाकी पूरा नहीं हुआ। मैं आंकड़ा दिए देती हूं। 3,58,000 का कुल लक्ष्य रखा गया था, 1,79,365 की पूर्ति हुई है। पिछले वर्ष का लक्ष्य भी 83,000 का रखा गया था, केवल 42,855 की पूर्ति हुई है। निश्चित तौर पर वे कारण जानना चाहेंगे कि क्यों यह पूर्ति नहीं हो पाई? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस टैक्नोलॉजी से विलेज पब्लिक टेलीफोन देने की बात सरकार ने की थी, वह टैक्नोलॉजी सक्सैसफुल नहीं हुई। वह टैक्नोलॉजी थी "मार" की —एम०ए०आर०आर० की और स्वयं प्रधान मंत्री के स्तर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री, आज के नहीं, श्री गुजराल जी के समय यह फैसला किया गया कि "मार" टैक्नोलॉजी को कतई डिस्कार्ड कर दिया जाए, आगे कोई आर्डर "मार" के ऊपर न दिया जाए। इसलिए "मार" टैक्नोलॉजी के असफल होने का बहुत बड़ा कारण इसमें रहा है और दूसरा कारण यह रहा है कि यह जो बेसिक टेलीफोन में प्राइवेट सैक्टर ने आना था, उन्होंने भी लक्ष्य विलेज पब्लिक टेलीफोन का लिया था, लेकिन

जैसा मैंने कहा है कि अभी बेसिक सेवा में [redacted] ही टेलीफोन ऑपरेटर आया है, इसलिए तमाम बेसिक वालों को दिए गए थे, वे भी अधूरे आपकी जानकारी बिल्कुल सही है और केवल जानकारी ही नहीं, इसके माध्यम से जो चिंता का भाव निकलता है, मैं उस चिंता को शेयर करती हूं और उसके समाधान में भी लगी हूं।

SHRI V.N. GADGIL: Sir, I would like to know from the hon. Minsiter what the total number of persons on the waiting list is. What is the total production of all telecom factories? How many telephone lines are being produced every year? The reply says that the telephone demands have been more than the earlier estimates. Why did the estimates go wrong? There has been some delay in the entry of private sector. What is the reason for the delay?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति मोहदय, एक ही सवाल में 4 सवाल गाडगिल जी ने पूछे हैं लेकिन मैं एक-एक का जवाब दे दूंगी। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट जानना चाहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह संख्या 2,75,761 है लेकिन इस 2,75,761 की संख्या के चलते हमने इस साल 36 लाख टेलीफोन देने का लक्ष्य रखा है। इसलिए यह वेटिंग लिस्ट तो इस साल क्लियर हो जाएगी। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। मैं आपको यह कह सकती हूं कि जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास है। इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी के कारण लक्ष्य पूर्ति में कमी नहीं रहेगी। तीसरा सवाल आपने पूछा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स अभी तक क्यों नहीं आ पाए हैं। यह काफी बड़ा सवाल है, इसमें कई दिक्कतें आ रही हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो वे बता रहे हैं वह कैश-फ्लो प्राइसेज की बता रहे हैं जिसके कारण वे कहते हैं कि जो प्रोजेक्शंस उन्होंने किए थे, वे प्रोजेक्शंस हे-वॉयर हो गए और उनको वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन छः ऑपरेटर्स में भी एक ऑपरेटर ने शुरू कर दिया है इंदौर में और बाकी जो 4 ऑपरेटर्स हैं, जो पंजाब में आने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में आने वाले हैं, महाराष्ट्र में आने वाले हैं, उनका काफी ज्यादा काम आगे बढ़ गया है। केवल एक ऑपरेटर ऐसा है जो राजस्थान सर्किल में आने वाला है, [redacted] ई काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन [redacted] टर्स है, उस एक के अलावा, जिनके [redacted], वे इस प्रयास में हैं कि वे जल्दी ये सेवाएं प्रारंभ कर सकें।

SHRI K.M. SAIFULLAH: Sir, I would like to know from the hon. Minister when she is going to reconstitute the Telephone Advisory Committees. In Andhra Pradesh its term is over four months ago. It is not reconstituted.

MR. CHAIRMAN: That question doesn't arise out of this.

SHRI K.M. SAIFULLAH: Sir, it is connected with the telephone facility. So, I want to know this.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह सवाल इसमें से नहीं निकलता लेकिन मैं माननीय सदस्य की चिंता इसलिए जायज़ मान लेती हूं क्योंकि टी०ए०सी० में एम०पीज० के नॉमिनीज़ रहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अभी तक टी०ए०सी० क्यों नहीं बनी? टी०ए०सी० सारी की सारी नहीं बनने वाली हैं। कुछ टी०ए०सी० का समय अभी बाकी है। इसलिए जो भी टी०ए०सी० बनेंगी, बजट सैशन के बाद हम उनको नोटिफाई करने वाले हैं। एम०पीज० को चिट्ठियां गई हैं, कुछ के नाम आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। जिनके नहीं आए हैं, उनको हम टेलीफोन पर कह रहे हैं कि नाम भिजवा दीजिए। बजट सैशन के बाद हम ये टी०ए०सी० बनाएंगे।

श्री ओम प्रकाश कोहली: माननीय सभापति महोदय, टेलीफोन ऑन डिमांड की बात तो ठीक है लेकिन यह अनुभव में आता है कि ओ०बी० जारी होने के बाद भी 3-3 महीने तक फोन नहीं लगाया जाता। ऐसे में फोन ऑन डिमांड का क्या अर्थ है? क्या ऐसा कोई नियम है कि ओ०बी० जारी होने के बाद एक निर्धारित अवधि के अंदर फोन लगा दिया जाएगा? अगर ऐसा कोई नियम है तो ओ०बी० जारी करने के कितने समय के भीतर फोन लगाना अनिवार्य है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कुल कितने ओ०बी० ऐसे पड़े हुए हैं और उन्हें कब तक क्लियर किया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, बहुत ही सही सवाल किया कोहली जी ने। मैंने स्वयं इसका उत्तर देना चाहा था क्योंकि टेलीफोन ऑन डिमांड के मायने यह नहीं कि एक कागज़ ओ०बी० का पकड़ा दिया जाए और अपने यहां से डिलीट कर दिया जाए कि हमने टेलीफोन

दे दिया। मेरी निगाह में टेलीफोन ऑन डिमांड के मायने यह हैं कि ओ०बी० के बाद टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट उसके घर लग जाए और उसमें करेंट आ जाए और वह चल जाए। इसके बीच का भी एक गैप होता कि ओ०बी० के बाद टेलीफोन लग जाता है और करेंट आने में समय लगता है। लेकिन मेरे लिए टेलीफोन ऑन डिमांड का मतलब है जब वह चालू हो जाए। जहां तक दिल्ली का सवाल है, यह समस्या ज्यादा दिल्ली में है। दिल्ली में नियम जरूर रखा गया है कि 15 दिन के भीतर ओ०बी० निकलने के अंदर-अंदर टेलीफोन लग जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने आंकड़ा मांगा तो मैं चौंक गई कि 40,000 से ज्यादा ओ०बी० ऐसे पड़े है जो 6-6 महीने हो गए और उन पर टेलीफोन नहीं लगा। कोहली जी ने शायद देखा होगा कि इसका बाकायदा एक चार्ट बनवाकर एक रेडर्वाइज़मेंट मैंने अखबारों में निकलवाया था। मैंने पूछा अधिकारियों से कि ये ओ०बी० देने का अर्थ क्या था अगर टेलीफोन लगना नहीं था। तो पहले उन्होंने कहा कि केबल्स नहीं हैं, कहीं पेयर्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केबल और पेयर नहीं हैं तो ओ०बी० दी क्यों? उन्होंने कहा कि अगर होम ओ०बी० नहीं देते तो हम पर यह आरोप लगता कि पिक एंड चूज़ हुआ है। एक नंबर ओ०बी० देने के बाद छठा नंबर दिया गया, दसवां नंबर दिया गया, बीच का क्यों नहीं दिया गया? तो हमने कहा कि इसमें जनता को विश्वास में लेना चाहिए और ये ओ०बी० हम किस कारण नहीं लगा पा रहे हैं और कब तक लगा पाएंगे, इस बारे में भी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। एक फुल-फ्लेज्ड एडवर्टाइज़मेंट गया डी०ओ०टी० की तरफ से जिसमें लिखा गया कि इस एरिया में जो ओ०बीज़ अभी तक नहीं लगीं, वे फलां तारीख तक लग जाएंगी और हमने 31 दिसम्बर का लक्ष्य रखा है कि ये जो 40,000 ओ०बीज़ आज बिना टेलीफोन लगे पड़ी हैं, इन सबके अंदर हम लोग टेलीफोन दे देंगे और टेलीफोन चालू कर देंगे।

श्री रामजीलाल: धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि 1997 तक जो टेलीफोन की मांगें को नहीं दे सके, 2002 तक आप देने की कोशिश करेंगी, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अभी हिसार के जी०एम० ने एक हफ्ता पहले ऐलान किया कि हम 31 मार्च तक सारे टेलीफोन ऑन डिमांड पर देंगे। महोदया, आप हरियाणा से हैं, हिसार को आप भलीभांति जानती हैं। वहां 17,000 लाईन का एक्सचेंज है जो कि पूरा हो चुका है और वेटिंग लिस्ट 4000 की वहां पड़ी हुई है। तो जब तक एक्सचेंज नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक वहां कैसे कनेक्शन देंगे? एक तो मेरा यह सवाल है।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि गांवों के अंदर टेलीफोन लग गए हैं और वहां पर पी०वी०सी० के घटिया तारें लगी हुई हैं। आजकल ओ०एफ०सी०, ऑप्टिकल फाईबर केबल जो आई हुई हैं, बहुत बढ़िया केबल हैं। क्या आप ये जो एक्सचेंज हैं हमारे गांवों के, उनमें ये बढ़िया केबल, ओ०एफ०सी० लगाने की कृपा करेंगे? क्या आप कह सकती हैं कि कब तक सारे एक्सचेंजों में ये तार लग जाएंगे क्योंकि ऐसा पता लगा है कि जहां ये तार लगी हैं, वहां टेलीफोन बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और पुरानी घटिया तार जहां लगी हैं, वहां के टेलीफोन वैसे ही खराब पड़े हैं। तो यह बताने की कृपा करें कि कब तक इन्हें लगाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, हिसार से संबंधित सवाल में तो आप भी इंट्रस्टेड होंगे, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दे देती हूं। जहां तक हिसार टेलीफोन एक्सचेंज का सवाल है, अब जी०एम० ने इनसे कहा है कि हम 31 मार्च तक दे देंगे। तो वह एक्सचेंज बढ़ाकर देंगे या उस एक्सचेंज की कैपेसिटी बढ़ाकर देंगे, यह आप उन पर छोड़ दीजिए। अगर 31 मार्च तक वे अपना आश्वासन पूरा नहीं करते तब आप कहिए कि 31 मार्च तक दिया हुआ आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया। मैंने जो कहा कि 2002 तक हम ऑन डिमांड टेलीफोन दे देंगे, उसमें निश्चित रूप से ये चीजें इन-बिल्ट हैं कि अगर कहीं एक्सचेंज की कैपेसिटी बढ़ानी है तो वह बढ़ाएंगे, अगर कहीं नए एक्सचेंज लगाने हैं, तो वह लगाएंगे,। लेकिन मैं रामजीलाल जी की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हरियाणा में नए सी०जी०एम० ने टेक-ओवर किया है श्री डी०पी०एस० सेठ ने और उन्हें बुलाकर मैंने हिदायत दी है और वे शायद अगले 15 दिनों में हरियाणा के तमाम सांसदों को बुलाएंगे और ये जो चीजें आपने मुझ से कही हैं, कहीं ऑप्टिकल फाईबर डालने की बात है, कहीं तार बदलने की बात है, मैंने उनसे कहा है कि हर सांसद की तकलीफ को वह स्वयं नोट कर लें और उसको कैसे पूरा करना है, उसमें कहां इक्विपमेंट चाहिए या जो भी सामग्री चाहिए, वह स्वयं ले सकते हैं या हमसे मांगना पड़े तो हमसे मांग सकते हैं। मेरे बीच-बचाव की जरूरत पड़े, तो वह भी मैं कर सकती हूं। लगभग 15 दिनों के अंदर हरियाणा के सांसदों की नए सी०जी०एम० मीटिंग बुलाने वाले हैं और यदि आप कुछ होमवर्क करना चाहें तो होमवर्क करके ले जाइए और उन्हें बता दीजिए। हरियाणा की टेलीफोन व्यवस्था में सुधार के लिए अलग से ऐहतियाती कदम मैंने उठाए हैं।